(b) No, Sir. The shortage of teachers in one subject does not prevent the teaching of other subjects. Moreover, the figures quoted in part (a) of the question are from the Report of the Education Commission of 1964-66, since when several measures to improve the situation have been taken and the shortage is being reduced gradually.

(c) Does not arise.

REORGANISATION OF EDUCATION SYSTEM

952. DR. A. G. SONAR : Will the Minister of EDUCATION be pleased to state :

(a) how many States have reorganised the Education systems on the pattern of Kothari Commission's Report;

(b) whether it is a fact that certain States have decided not to fall in line with other States as per Kothari Commission Report;

(c) whether Government could bind them to accept the recommendations of the Commission; and

(d) if not, whether different types of patterns will not thereby continue in different States ?

THE MINISTER OF EDUCATION (DR. TRIGUNA SEN) : (a) So far Kerala is the only State which has fully changed over to the pattern of 10+2+6 recommended by the Education Commission. The propsal is, however, under the consideration of the other State Governments.

(b) Government has no information.

(c) No, Sir.

(d) Government hope that, within a few years, all the State Governments will adopt the pattern of school and college classes recommended by the Education Commission

उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त द्वारा टाटा मर्सीडीज बसोंपर कमीशन का लिया जाना

953. **श्री मधु लिमये** : क्या **परिवहन तथा नौवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन आयुक्त को टाटा मर्सीडीज से कमीशन के रूप में 3 लाख 40 हजार रुपये का चैक प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस वर्ष राज्य सरकार ने टाटा मर्सीडीज बसों की कीमत के रूप में 1 करोड़ 74 लाख रुपये की राशि दी थी और यह कमीशन इसी सम्बन्ध में दिया गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि जब परिवहन आयुक्त ने कमीशन की इस राशि को सरकारी कोष में जमा कराने का आदेश दिया तो एक समस्या उत्पन्न हो गई कि इस धन को किस शीर्षक के अन्तर्गत जमा किया जाये, क्योंकि ऐसे कमीशन का पता पहली बार ही लगा था;

(घ) क्या यह भी सच है कि ऐसी प्रत्येक खरीद पर राज्य सरकार को प्रति वर्ष ऐसा कमीशन दिया जाता रहा है;

(ङ) यदि हां, तो पहले ऐसा कमीशन किस शीर्षक के अन्तर्गत जमा किया गया था अथवा उस अधिकारी का ब्यौरा क्या है, जो इस राशि का गबन करता रहा है; और

(च) क्या सरकार का विचार राज्य सरकार द्वारा टाटा मर्सीडीज के साथ किये गये प्रत्येक सौदे की जांच कराने तथा सब तथ्यों का पता लगाने का है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) (क) से (च) अपेक्षित सूचना उत्तर प्रदेश सरकार से